[2010] 15 (एडीडीएल) एससी.आर. 1126

श्रीमती. गीता

व

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य।

(सिविल अपील संख्या 10607 की 2010)

14 दिसंबर 2010

(जीएस सिंघवी और अशोक कुमार गांगुली, जेजेजे)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम , 1961 - उ.प्र. पंचायत कानून (संशोधन) अधिनियम, 2007 - सी एसएस.7(3), 9(2) और 9ए - 1961 अधिनियम प्रत्येक क्षेत्र में प्रमुख, उप-प्रमुख (वरिष्ठ उप-प्रमुख और कनिष्ठ उप-प्रमुख) के कार्यालयों के लिए प्रावधान करता है। पंचायत - 1961 अधिनियम में किया गया संशोधन - संशोधन अधिनियम की धारा 7(3) में गैर-अस्थिर खंड - की व्याख्या - क्या 1961 अधिनियम में संशोधन के बाद , वरिष्ठ उप-प्रमुख का अधिकार और प्रमुख के कर्तव्यों का निर्वहन जीवित रहा या क्या प्रमुख का पद खाली होने पर और जब तक कोई नया प्रमुख निर्वाचित नहीं हो जाता या फिर से कार्यालय में नहीं आ जाता, तब तक जिला मजिस्ट्रेट किसी निर्वाचित सदस्य को प्रमुख के रूप में नामित कर सकता है - माना गया: संशोधन अधिनियम ने उक्त पद को समाप्त कर दिया क्षेत्र पंचायतों से उप-प्रमुख की और बशर्ते कि ऐसे मामलों में जहां प्रमुख का पद खाली हो , जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी व्यवस्था करनी होगी जैसा वह उचित समझे- हालांकि , एस के अनुसार। 7(3), उप-प्रमुख अभी भी अपने कार्यकाल के अंत तक पद पर बने रहेंगे , लेकिनगैर-अस्थिर खंड का संचालन। 7(3) विधायिका की मंशा के अधीन होगा , और इसकी व्याख्या अधिनियम की योजना और उस उद्देश्य के अनुरूप की जानी चाहिए जिसके लिए इसे अधिनियमित किया गया था - प्रावधान में 'पद पर बने रहना' का अर्थ यह होगा कि संशोधन अधिनियम में उप-प्रमुख के पद को समाप्त करने के बावजूद, जो लोग इस तरह के संशोधन से पहले उप-प्रमुख के रूप में चुने गए थे , वे अपना कार्यकाल समाप्त होने तक उप-प्रमुख के रूप में बने रहेंगे - अभिव्यक्ति 'ऐसे ही' की गई है सावधानी बरतने और ज़ोर देने के लिए जोड़ा गया ,उप-प्रमुख की निरंतरता केवलउप-प्रमुख के

पद पर बने रहने तक ही सीमित है - संशोधन अधिनियम की धारा 7(3) में 'जैसे कि उक्त अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया था' अभिव्यक्ति केवल वहीं लागू होती है,

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2010] 15 (एडीडीएल) एससी.आर. 1127

जहां सामान्य संशोधन का रास्ता है 1961 के अधिनियम में , उप-प्रमुख शब्दों को हटा दिया गया है - प्रतिवादी का विपरीत तर्क कि उप-प्रमुख अधिनियम के पूर्व-मौजूदा प्रावधानों की धारा 82 और 83 के तहत सभी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करना जारी रखेंगे। संशोधन अधिनियम द्वारा उन प्रावधानों का स्पष्ट विलोपन स्वीकार नहीं किया जा सकता - यदि उस तर्क को स्वीकार किया जाता है, तो एसएस के पूर्व-मौजूदा प्रावधान। 82 और 83 को पुनर्जीवित किया जाएगा और एस.एस. 9(2) और 9ए, संशोधन के माध्यम से लाए गए और इसमें जिला मजिस्ट्रेट को प्रमुख का कार्यालय खाली होने पर या प्रमुख कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होने पर व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया , जो अव्यवहारिक होगा - क़ानून की व्याख्या - सामंजस्यपूर्ण व्याख्या.

क़ानून की व्याख्या - गैर-अप्रत्याशित उपवाक्य- का तात्पर्य और अर्थ - चर्चा की गई।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम , 1961 में प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में प्रमुख, उप-प्रमुख (वरिष्ठ उप-प्रमुख और कनिष्ठ उप-प्रमुख) और प्रत्येक जिला पंचायत में अध्यक्ष और उप-अध्यक्ष के कार्यालयों का प्रावधान किया गया था। अधिनियम को यूपी पंचायत कानून (संशोधन) अधिनियम , 2007 के माध्यम से संशोधित किया गया था। परिणामस्वरूप , उक्त संशोधन अधिनियम की धारा 7(3) की तुलना में धारा 9(2) और 9ए की व्याख्या से संबंधित कानून के सामान्य प्रश्न उठे।

विवाद इस बात पर उठा कि क्या 1961 के अधिनियम में संशोधन के बाद प्रमुख के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए वरिष्ठ उप-प्रमुख का अधिकार और प्राधिकार बच गया है या क्या जिला मजिस्ट्रेट प्रमुख के पद पर रहते हुए एक निर्वाचित सदस्य को प्रमुख के रूप में नामित कर सकता है? रिक्त हो गया और जब तक कोई नया प्रमुख निर्वाचित नहीं हो गया या कार्यालय फिर से शुरू नहीं हो गया।

अपीलकर्ताओं ने संशोधन अधिनियम की धारा 9(2) और 9ए के तहत अपना मामला रखा। उन्होंने दावा किया कि उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार , प्रमुख का पद रिक्त होने पर प्रमुख की नियुक्ति करना जिला मजिस्ट्रेट का काम है और उप-प्रमुख ऐसा कर सकता है। संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद , प्रमुख का पद रिक्त होने पर प्रमुख के रूप में कार्यों का निर्वहन स्वचालित रूप से नहीं होगा।

इसके विपरीत , प्रतिवादी ने माना कि प्रमुख का पद खाली होने पर उप-प्रमुख स्वचालित रूप से प्रमुख बन जाएगा, जैसा कि संशोधन अधिनियम लागू होने से पहले स्थिति थी; और यह भी कि यह संशोधित धारा 7(3) में गैर-अस्थिर खंड के तहत उचित है। उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि संशोधन से पहले, वरिष्ठ उप-प्रमुख के अधिकारों में प्रमुख का कार्यालय खाली होने पर कार्य करने और प्रमुख के कर्तव्यों का निर्वहन करने का अधिकार शामिल था ; और उक्त धारा 7(3) में शब्द "इस रूप में पद पर बने रहना" उप-प्रमुख को वरिष्ठ उप-प्रमुख के सभी कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने का अधिकार देता है जैसा कि संशोधन अधिनियम पेश होने से पहले प्रचलित था।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए

आयोजित: 1.1. पंचायतों को विनियमित करने वाले राज्य कानूनों को संविधान के भाग IX के प्रावधानों के अनुरूप बनाने के लिए 2007 में संशोधन अधिनियम पेश किया गया था। संशोधन अधिनियम पेश होने से पहले, 1961 अधिनियम में प्रावधान था कि यदि प्रमुख का पद खाली हो जाता है , तो उप-प्रमुख नए प्रमुख की नियुक्ति होने तक प्रमुख के कार्यों का निर्वहन करेगा। संशोधन अधिनियम ने क्षेत्र पंचायतों से उप-प्रमुख के उक्त पद को समाप्त कर दिया , बशर्ते कि ऐसे मामलों में जहां प्रमुख का पद रिक्त हो, जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी व्यवस्था करनी होगी जैसा वह उचित समझे। हालाँकि, अनुभाग के अनुसार

7(3), उप-प्रमुख अभी भी अपने कार्यकाल के अंत तक पद पर बने रहेंगे। [पैरा 29,31] [1139-बी; जीएच; 1140-ए]

1.2. धारा 7(3) एक गैर-प्रतिरोधी खंड से शुरू होती है , अर्थात। "इस अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान में और किसी भी विपरीत सामग्री के बावजूद।" उक्त प्रावधान दो प्रश्न उठाता है जिनका उत्तर देने की आवश्यकता है: क्या गैर-अस्थिर खंड संशोधन अधिनियम के बाकी प्रावधानों पर प्रबल होगा , और किस हद तक अभिव्यक्ति "कार्यालय में कैसे बनी रहेगी" इस प्रकार" प्रावधान में अर्थ लगाया जाना है। इस न्यायालय के समक्ष बड़ी संख्या में निर्णयों में गैर-अस्पष्ट धाराओं की व्याख्या विचार के लिए आई है। गैर-अस्थिर खंड के अभिप्राय और अर्थ पर इस न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई लगातार राय को ध्यान में रखते हुए , यह स्पष्ट है कि संशोधित अधिनियम की धारा 7(3) में गैर-विषयक खंड का संचालन इरादे के अधीन होगा। विधायिका की, और इसकी व्याख्या अधिनियम की योजना और उस उद्देश्य के अनुरूप की जानी चाहिए जिसके लिए इसे अधिनियमित किया गया था। [पैरा 32, 33 और 40] [1140-बीडी; 1142-एफ]

1.3. दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित फैसले में कहा कि धारा 7(3) में गैर-अस्थिर खंड को संशोधन अधिनियम के अन्य प्रावधानों को पूरी तरह से समाप्त करने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और उप-प्रमुख जो संशोधन से पहले चुने गए थे अधिनियम ऐसे ही कायम रहेगा जैसे कि संशोधन अधिनियम पूरी तरह से अधिनियमित ही नहीं हुआ हो। हालाँकि , इस न्यायालय के कई निर्णयों को ध्यान में रखते हुए , यह माना जाता है कि धारा 7(3) में गैर-अप्रत्याशित कारण उप-प्रमुख को "इस तरह पद पर बने रहने" की अनुमति देने की सीमा तक सीमित होगा। मानो उक्त अधिनियम अधिनियमित ही नहीं किया गया हो।" 'इसी प्रकार पद पर बने रहना' शब्द का अर्थ यह होगा कि संशोधित अधिनियम में उप-प्रमुख के पद को समाप्त करने के बावजूद, जो लोग पहले उप-प्रमुख के रूप में चुने गए थे।

इस तरह का संशोधन ही जारी रहेगा यानी उप-प्रमुख के रूप में उसका कार्यकाल समाप्त होने तक। यह अभिव्यक्ति सावधानी के तौर पर और इस बात पर जोर देने के लिए जोड़ी गई है कि उप-प्रमुख की निरंतरता केवल उप-प्रमुख के पद पर बने रहने तक ही सीमित है। [पैरा 42, 43, 44] [1143-एई)

1.4. प्रतिवादी का विपरीत तर्क और जो उच्च न्यायालय के अनुरूप था , वह यह था कि उप-प्रमुख अधिनियम के पूर्व-मौजूदा प्रावधानों की धारा 82 और 83 के तहत सभी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करना जारी रखेंगे , भले ही उन प्रावधानों को स्पष्ट रूप से हटा दिया गया हो। संशोधन अधिनियम. इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता. यदि उस तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो उस स्थिति में, जो प्रावधान संशोधन के माध्यम से स्पष्ट रूप से हटा दिए गए हैं , जैसे धारा 82 और 83 के पहले से मौजूद प्रावधान , पुनर्जीवित हो जाएंगे। धारा 9(2) और 9ए, संशोधन के माध्यम से लाई गईं और इस तरह प्रमुख का कार्यालय खाली होने पर जिला मजिस्ट्रेट को व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया [धारा 9(2)] या जब प्रमुख कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो [धारा 9ए]] अव्यवहार्य होगा. इसलिए , संशोधित अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या के लिए , धारा 7(3) में गैर-अस्थिर खंड को एक प्रतिबंधित अर्थ दिया जाना चाहिए ताकि संशोधित अधिनियम के अन्य प्रावधानों के साथ टकराव न हो। [पैरा 45 और 46] [1143-एफएच]

1.5. संशोधित अधिनियम की धारा 7(3) में 'मानो उक्त अधिनियम अधिनियमित ही नहीं किया गया' अभिव्यक्ति केवल वहां लागू होती है जहां उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला अधिनियम 1961 के सामान्य संशोधन के माध्यम से , उप-प्रमुख शब्द हटा दिए गए हैं। इसलिए, वर्तमान मामले में जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा धारा 9(2) और 9ए के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित आदेशों की पुष्टि की जाती है। [पैरा 47,48] [1144-बीडी]

अश्विनी कुमार घोष एवं अन्य। वी अरबिंद बोस और अन्य। एआईआर

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2010] 15 (एडीडीएल) एससी.आर. 1131

1952 एसजी 369; डोमिनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य व श्रृनबल ए.ईरानी एवं अन्य एआईआर 1954 एससी 596 - का अनुसरण किया गया।

ए.जी. वरदराजुलु एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य (1998) 4 एससीसी 231: /सीएलसीआई बैंक लिमिटेड बनाम सिडू लेदर्स लिमिटेड एवं अन्य। (2006) 10 एससीसी 452: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम केरल राज्य एवं अन्य। (2009) 4 एससीसी 94-पर भरोसा किया गया।

भानुमती आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य , इसके प्रमुख सचिवएवं अन्य के माध्यम से। (2010) 7 स्केल 398; माधव राव सिंधिया बनाम भारत संघ एवं अन्य (1971) 1 एससीजी 85; चंदावरकर सीता रत्न राव बनाम आशालता एस , गुरम (1986) 4 एससीसी 447; भारत संघ एवं अन्य बनाम जीएम कोकिल एवं अन्य 1984 (सप्लीमेंट) एससीसी 196 - संदर्भित।

केस कानून संदर्भ:

(2010) 7 स्केल 398	**संदर्भित**	**पारा 5, 19, 30**
एआईआर 1952 एससी 369	**अनुसरण**	**पारा 34**
एआईआर 1954 एससी 596	**अनुसरण**	**पारा 35**
(1986) 4 एससीसी 447	**संदर्भित**	**पारा 36**
(1998) 4 एससीसी 231	**भरोसा**	**पारा 37**
(1971) 1 एससीसी 85	**संदर्भित**	**पारा 37**
(2006) 10 एससीसी 452	**भरोसा**	**पारा 38**
(2009) 4 एससीसी 94	**भरोसा**	**पारा 39**
(1986) 4 एससीसी 447	**संदर्भित**	**पारा 41**
1984 (सप्प) एससीसी 196	**संदर्भित**	**पारा 41**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2010 की सिविल अपील संख्या 10607

उच्च के निर्णय एवं आदेश दिनांक 26.08.2010 से

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2010] 15 (एडीडीएल) एससी.आर. 1132

रिट याचिका संख्या, 40262 (एम/) में इलाहाबाद में न्यायिक न्यायालय

सी.ए. नंबर 10608, 10609, 10610. 10611, 10612 और 10613 ओ1 बी 2010

एच एल अग्रवाल , शोभा दिक्षित , पीएन मिश्रा , दिनेश कुमार तिवारी , रजत शर्मा , चंदन कुमार , अशोक कुमार सिंह,खवइराकपम, नवीन सिंह, देवव्रत, मंगलेश चौबे, हरीश पांडे, उपस्थित पार्टियो के लिय,

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

गांगुली, जे. 1. इन सभी मामलों में छुट्टी दी जाती है। डी सात अपीलों का यह बैच कानून के सामान्य प्रश्न उठाता है जिनका इस फैसले में निपटारा किया गया है।

2. प्रत्येक मामले में तथ्य अलग-अलग नोट किए गए हैं:

सी.ए.न. 2010की10607 @ (एसएलपी संख्या 26113/2010)

3. फरवरी 2006 में, श्रीमतीशांता देवी को क्षेत्र पंचायत जहानागंज , जिला आज़मगढ़ के चुनाव में प्रमुख चुनी गईं।

4. 2007 में, संशोधन अधिनियम संख्या के माध्यम से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम , 1961 (इसके बाद 1961 अधिनियम कहा जाएगा) में एक संशोधन किया गया था। राज्य अधिनियम को भाग IX के साथ संगत बनाने के लिए 2007 का 44 (इसके बाद इसे संशोधन अधिनियम कहा जाएगा) जिसमें पंचायतों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान शामिल हैं।

5. कुछ गंभीर आरोपों के मद्देनजर। श्रीमती शांता देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। श्रीमती शांता देवी ने यूपी पंचायत कानून (संशोधन) अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

2007 दिनांक 20.08.2007 (जो बाद में यूपी पंचायत कानून (संशोधन) अधिनियम, 2007 यानी संशोधन अधिनियम बन गया), एक रिट याचिका दायर करके, जिसे 6.02.2009 को खारिज कर दिया गया था। जिसके विरुद्ध उसने इस न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की। विशेष अनुमति याचिका को भी भानुमति आदि वनाम उत्तर प्रदेश राज्य नामक मामले में दिनांक 4.05.2010 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने

प्रधान सचिव एवं अन्य के माध्यम से , 2010 (7) स्केल 398, संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को कायम रखा।

6. तदनुसार, जिला मजिस्ट्रेट ने श्रीमतीशांता देवी को रोक दिया। उनके खिलाफ पारित अविश्वास प्रस्ताव और उच्च न्यायालय के दिनांक 6.02.2009 के आदेश के आलोक में प्रमुख के रूप में कार्य करने से रोक दिया गया है। इसलिए प्रमुख का पद रिक्त हो गया। जिला मजिस्ट्रेट ने संशोधन अधिनियम की धारा 9(2) और उसके तहत नियमों के तहत उन्हें प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक 2.07.2010 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता को इस पद के लिए नामित किया। उप-प्रमुख के पद पर कार्यरत छठे प्रतिवादी ने जिला मजिस्ट्रेट के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय , इलाहाबाद (सीएमडब्ल्यूपी संख्या 40262/2010) में एक रिट याचिका दायर की।

7. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित सामान्य निर्णय दिनांक 26.08.2010 (सीएमडब्ल्यूपी संख्या, 40262/2010 के साथ 44538/2010 के लिए) के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया। और उप-प्रमुख को प्रमुख के रूप में बने रहने की अनुमति दी। इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय का रुख किया।

<u>सी.ए.न. 2010 का 10608 (@ एसएलपी नंबर 26447/201</u>

8. 22.10.2005 को अपीलार्थी को सामान्य सीट से क्षेत्र पंचायत मझवां , मिर्ज़ापुर से ब्लॉक विकास समिति के सदस्य के रूप में चुना गया था। सातवें प्रतिवादी को वरिष्ठ उप-प्रमुख के रूप में चुना गया। प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया जिसके फलस्वरूप प्रमुख का पद रिक्त हो गया। जिलाधिकारी प्रमुख के कार्यों के निर्वहन के लिए सातवें प्रतिवादी को नियुक्त किया।

जिलाधिकारी प्रमुख के कार्यों के निर्वहन के लिए सातवें प्रतिवादी को नियुक्त किया।

9. अपीलकर्ता ने प्रमुख के पद पर सातवें प्रतिवादी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका (सीएमडब्ल्यूपी संख्या 44538 2010) दायर की। इसे उच्च न्यायालय ने दिनांक 26.08.2010 (सीएमडब्ल्यूपी संख्या 40262/2010 के साथ 44538/2010 के लिए) के माध्यम

से खारिज कर दिया था , यह मानते हुए कि कानून के प्रावधानों के तहत , वरिष्ठ उप-प्रमुख एकमात्र अधिकृत व्यक्ति था। विधिवत निर्वाचित प्रमुख की अनुपस्थिति में प्रमुख के रूप में कार्य करना। उस फैसले को चुनौती देते हुए, संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी।

2010 की सिविल अपील संख्या 10609 @(एसएलपी संख्या 26201/2010)

10. 27.02.2006 को श्रीमती. पुष्पा को जिले की क्षेत्र पंचायत मोतिगरपुर का प्रमुख नियुक्त किया गया। सुल्तानपुर. चौथे प्रतिवादी को उप-प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। श्रीमती पुष्पा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था ,4.01.2008 को श्रीमती पुष्पा ने 20.08.2007 के अध्यादेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करके चुनौती दी, जिसे 6.02.2009 को खारिज कर दिया गया। श्रीमती पुष्पा ने इस अदालत के समक्ष एक एसएलपी दायर की, जिसे 4.05.2010 के फैसले - भानुमती केस (सुप्रा) द्वारा खारिज कर दिया गया।

11. इसलिए, जिला मजिस्ट्रेट ने श्रीमती पुष्पा को बर्खास्त कर दिया। 20.07.2010 को प्रमुख पद से हटा दिया गया और संशोधन अधिनियम की धारा 9(2) के प्रावधानों के तहत आदेश दिनांक 21.07.2010 द्वारा अपीलकर्ता को इस पद के लिए नामांकित किया गया।

12. व्यथित होकर चौथे प्रतिवादी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका जी (नंबर 7272(एमबी)2010) दायर की। उच्च न्यायालय ने दिनांक 26.08.2010 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया और अपीलकर्ता को प्रतिवादी के कामकाज में हस्तक्षेप करने से रोक दिया। इसलिए, इस अदालत के समक्ष वर्तमान अपील है,

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2010] 15 (एडीडीएल) एससी.आर. 1135

2010 की सिविल अपील संख्या 10610 @एसएलपी संख्या 27470/2010

13. श्रीमती सोनू देवी 27.02.2006 को क्षेत्र पंचायत, अखण्डनगर, जनपद सुलतानपुर के चुनाव में प्रमुख पद पर निर्वाचित हुईं। छठे प्रतिवादी को उप-प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। श्रीमती सोनू देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था. 17.12.2007 को श्रीमती सोनू देवी ने 20.08.2007 के अध्यादेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका

दायर करके चुनौती दी , जिसे 6.02.2009 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद श्रीमति सोनू देवी ने इस न्यायालय के समक्ष एक एसएलपी दायर की , जिसे भानुमति मामले (सुप्रा) में दिए गए दिनांक 4.05.2010 के फैसले द्वारा खारिज कर दिया गया।

14. इसके बाद, जिला मजिस्ट्रेट ने 19.07.2010 को श्रीमति सोनू देवी को प्रमुख पद से बर्खास्त कर दिया। तथा अपीलार्थी को उक्त पद हेतु नामांकित किया गया। व्यथित होकर , छठे प्रतिवादी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका (संख्या 7626(एम/बी)/2010) दायर की। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 7272/2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 26.08.2010 के फैसले पर भरोसा करते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया। उच्च न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट के दिनांक 19.07.2010 के आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी। अपीलकर्ता को प्रमुख के काम की देखभाल करने से रोक दिया गया और छठे प्रतिवादी को अदालत के अगले आदेश तक या प्रमुख चुने जाने तक प्रमुख के कार्यों का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया। इसलिए, इस अदालत के समक्ष वर्तमान अपील है,

15. फरवरी 2006 में, क्षेत्र पंचायत सिधौली, जिला सीतापुर के चुनाव में श्रीमति सुशीला देवी (तीसरी प्रतिवादी) को प्रमुख नियुक्त किया गया। चौथे प्रतिवादी को उप-प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। 2008 में श्रीमती सुशीला देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर करके 20.08.2007 के संशोधन अध्यादेश को चुनौती दी थी जिसे 6.02.2009 को खारिज कर दिया गया था , उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष एक एसएलपी दायर की और उसी भानुमति मामले (सुप्रा) में दिनांक 4.05.2010 के फैसले द्वारा खारिज कर दिया गया था।

16. परिणामस्वरूप, जिला मजिस्ट्रेट ने 29.07.2010 को श्रीमती सुशीला देवी को प्रमुख पद से बर्खास्त कर दिया और अपीलकर्ता को 30.07.2010 को इस पद के लिए नामित किया। व्यथित होकर चौथे प्रतिवादी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका (संख्या 7604 (एम/बी)2010) दायर की। उच्च न्यायालय ने सीएमडब्ल्यूपी संख्या 7272/2010 में फैसले पर भरोसा करते हुए दिनांक 26.08.2010 को अंतरिम आदेश पारित किया और चौथे

प्रतिवादी को प्रमुख के रूप में कार्य करने का निर्देश दिया और अपीलकर्ता को चौथे प्रतिवादी के कामकाज में हस्तक्षेप करने से रोक दिया। अत: अपील प्रस्तुत करें।

17. अपीलार्थी को क्षेत्र पंचायत , भलुआरी जिला-देवरिया का सदस्य चुना गया था। क्षेत्र पंचायत, भलुअनी जिला-देवरिया के प्रमुख के विरुद्ध दिनांक 6.8.2010 को अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप उक्त पद रिक्त हो गया। दिनांक 11.8.2010 को जिलाधिकारी ने ब्लॉक प्रमुख के रिक्त पद पर सातवें प्रतिवादी को नामित किया।

<u>2010 की सिविल अपील संख्या 10613 @ एसएलपी संख्या 35231/2010 (2010 की सीसी संख्या 17260)</u>

18. आठवें प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका (संख्या 50547/2010) दायर करके उक्त आदेश को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने सीएमडब्ल्यूपी संख्या 40262/2010 में पारित आदेश का पालन किया और दिनांक 11.8.2010 के फैसले पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। इसलिए , अपीलकर्ता (जो उच्च न्यायालय के समक्ष एक पक्ष नहीं था) ने इस अदालत के समक्ष वर्तमान अपील दायर की।

<u>2010 की सिविल अपील संख्या 10612 @ एसएलपी 27404/2010</u>

19. श्रीमती बिंदु देवी फरवरी 2006 में क्षेत्र पंचायत-फ्रीदाबाद , जिला जौनपुर की प्रमुख चुनी गईं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर करके दिनांक 20.8.2010 के संशोधित अध्यादेश को चुनौती दी , और इसे 6.2.2009 को खारिज कर दिया गया , उन्होंने इसे इस न्यायालय के समक्ष एक एसएलपी के माध्यम से चुनौती दी , जिसे भी भानुमती मामले (सुप्रा) मे दिये गये फैसला दिनांक 4.05.2010 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया।

20. इसके बाद, जिला मजिस्ट्रेट ने 19.7.2010 को श्रीमति बिंदु देवी को प्रमुख पद से बर्खास्त कर दिया और अपीलकर्ता को उक्त पद के लिए नामांकित किया गया। व्यथित होकर सातवें प्रतिवादी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका (संख्या 44066/2010) दायर की। उच्च न्यायालय ने सीएमडब्ल्यूपी संख्या 40262/2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के

फैसले पर भरोसा करने के बाद , दिनांक 28.8.2010 के आक्षेपित फैसले के तहत जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया।

21. इसलिए वर्तमान अपील।

22. इन अपीलों में उठने वाले कानून के सामान्य प्रश्न संशोधन अधिनियम की धारा 7(3) की तुलना में धारा 9(2) और 9ए की व्याख्या से संबंधित हैं।

23. सटीक सवाल यह है कि क्या 1961 के अधिनियम में संशोधन के बाद , प्रमुख के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए वरिष्ठ उप-प्रमुख का अधिकार और प्राधिकार जीवित रहेगा या क्या जिला मजिस्ट्रेट एक निर्वाचित सदस्य को प्रमुख के रूप में नामित कर सकता है जब प्रमुख का पद खाली हो जाता है और जब तक नया प्रमुख निर्वाचित नहीं हो जाता है या कार्यालय फिर से शुरू नहीं कर देता है।

24. प्रतिवादी द्वारा उठाया गया एक तर्क यह है कि जब प्रमुख का पद रिक्त हो जाता है तो उप-प्रमुख स्वचालित रूप से प्रमुख बन जाएगा , जैसा कि शस्त्रागार अधिनियम लागू होने से पहले स्थिति थी। यह भी आग्रह किया गया कि यह संशोधित धारा 7(3) के तहत उचित है। धारा 7(3) इस प्रकार है:

7. प्रमुख और उपप्रमुख-

(1) XXX

(2) XXX

(3) "इस अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान में किसी भी विपरीत बात के बावजूद , जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश पंचायत कानून (संशोधन) अधिनियम , 2007 के प्रारंभ होने से पहले उप-प्रमुख के पद के लिए चुने गए लोग अपने कार्यकाल की समाप्ति तक इस पद पर बने रहेंगे जैसे कि उक्त अधिनियम अधिनियमित नहीं हुआ था।

25. उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि शब्द "पद पर बने रहना" उप-प्रमुख को वरिष्ठ उप-प्रमुख के सभी कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने का अधिकार देता है जैसा कि संशोधन अधिनियम पेश होने से पहले प्रचलित था। संशोधन से पहले , वरिष्ठ के अधिकार उप-प्रमुख में प्रमुख का कार्यालय खाली होने पर कार्य करने और प्रमुख के कर्तव्यों का निर्वहन करने का अधिकार शामिल था। उत्तरदाताओं के इस तर्क को उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया , यही कारण है कि अपीलकर्ताओं ने इस न्यायालय के समक्ष अपीलों का वर्तमान बैच दायर किया।

26. हालांकि, अपीलकर्ताओं ने संशोधन अधिनियम की धारा 9(2) और 9ए के तहत अपना मामला रखा। 9(2) और 9ए के प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं:

"9. प्रमुख एवं उपप्रमुख का कार्यकाल-

(1) XXX

(2) जहां प्रमुख का पद रिक्त है , वहां जिला मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा प्रमुख के निर्वाचित होने तक प्रमुख के कार्यों के निर्वहन के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकता है जो वह उचित समझे।

9ए. कुछ मामलों में अस्थायी व्यवस्था- जब प्रमुख अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है , तो जिला मजिस्ट्रेट , आदेश द्वारा, ऐसी व्यवस्था कर सकता है, जो वह उचित समझे, उसके कार्यों के निर्वहन के लिए प्रमुख उस तारीख तक जब तक प्रमुख अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू नहीं करता।

27. अपीलकर्ताओं ने दावा किया कि उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार ,प्रमुख का पद रिक्त होने पर प्रमुख नियुक्त करने के लिएसंशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद , जिला मजिस्ट्रेट दवरा प्रमुख का पद रिक्त होने पर और उप-प्रमुख स्वचालित रूप से प्रमुख के रूप में कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकते थे।

28. ये पार्टियों के प्रतिद्वंद्वी विवाद हैं.

29. कोर्ट ने यह पाया कि पंचायतों को विनियमित करने वाले राज्य कानूनों को संविधान के भाग IX के प्रावधानों के अनुरूप बनाने के लिए 2007 में संशोधन अधिनियम पेश किया

गया था। 2007 के संशोधित अधिनियम में वस्तुओं और कारणों के विवरण का प्रासंगिक भाग पढ़ता है:

"वस्तुओं और कारणों का विवरण

संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम , 1947 (1947 का यूपी अधिनियम संख्या 26) प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रधान और उप-प्रधान के कार्यालयों और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यूपी अधिनियम संख्या 33) का प्रावधान करता है।प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में प्रमुख , उप-प्रमुख (वरिष्ठ उप-प्रमुख और कनिष्ठ उप-प्रमुख) और प्रत्येक जिला पंचायत में अध्यक्ष और उप-अध्यक्ष के कार्यालयों का प्रावधान किया गया। इसमें उन कार्यालयों के प्रावधानों को हटाने के लिए उक्त अधिनियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया , जिनके संबंध में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है , अर्थात् उप-प्रधान, उप-प्रमुख (वरिष्ठ उप-प्रमुख और कनिष्ठ उप-प्रमुख) के कार्यालय और उप-ध्याक्ष,"

30. यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को इस न्यायालय ने भानुमती मामले (सुप्रा) में बरकरार रखा है।

31. संशोधन अधिनियम पेश होने से पहले , 1961 जी अधिनियम में प्रावधान था कि यदि प्रमुख का पद खाली हो जाता है , तो उप-प्रमुख नए प्रमुख की नियुक्ति होने तक प्रमुख के कार्यों का निर्वहन करेगा। हालाँकि , संशोधन अधिनियम ने क्षेत्र पंचायतों से उप-प्रमुख के उक्त पद को समाप्त कर दिया और यह प्रावधान किया कि जिन मामलों में का पदखाली हो गया , जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी व्यवस्था करनी थी जो वह उचित समझे। हालाँकि , धारा 7(3) के अनुसार। उप-प्रमुख अभी भी अपने कार्यकाल के अंत तक पद पर बने रहेंगे।

32. धारा 7(3) एक गैर-अस्थिर खंड से शुरू होती है , अर्थात "इस अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान में किसी भी विपरीत बात के बावजूद।" उक्त प्रावधान दो प्रश्न उठाता है जिनका उत्तर दिया जाना आवश्यक है:

(ए) क्या गैर-अस्थिर खंड संशोधन अधिनियम के बाकी प्रावधानों पर प्रभावी होगा और किस हद तक?

(बी)अभिव्यक्ति "इसी रूप में पद पर बने रहेंगे" का अर्थ कैसे लगाया जाए ?

33. इस न्यायालय के समक्ष बड़ी संख्या में निर्णयों में गैर-अस्थिर खंडों की व्याख्या विचार के लिए आई है।

34. अश्विनी कुमार घोष एवं अन्य बनाम अरबिंद बोसएवं अन्य , एएनआर 1952 एससी 369 में रिपोर्ट की गई, इस कोर्ट की एक संविधान पीठ ने मुख्य न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री के माध्यम से बोलते हुए कहा कि गैर-अस्थिर खंड को किसी भी प्रासंगिक मौजूदा कानून में "कुछ भी शामिल" को ओवरराइड करने के रूप में पढ़ा जा सकता है। नये अधिनियम के साथ असंगत है। लेकिन उनके आधिपत्य ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी क़ानून के अधिनियमित भाग को , जहां यह स्पष्ट है , गैर-अस्थिर खंड को नियंत्रित करने के लिए लिया जाना चाहिए , जहां दोनों को सामंजस्यपूर्ण रूप से नहीं पढ़ा जा सकता है (पृष्ठ 377 देखें)।

35. फिर से इस न्यायालय की एक अन्य संविधान पीठ के फैसले में। डोमिनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य व वी. श्रीनबाई ए. ईरानी एवं अन्य, एआईआर 1954 एससी 596 में रिपोर्ट की गई, भगवती जे. ने पैरा 10 में निम्नानुसार देखा:

".. हालांकि आम तौर पर गैर-विषयक खंड और अनुभाग के ऑपरेटिव भाग के बीच एक करीबी सन्निकटन होना चाहिए , गैर-विषयक खंड को जरूरी नहीं है और ऑपरेटिव भाग एक तरह से सह-व्यापक होना चाहिए

ताकि किसी अधिनियम की स्पष्ट शर्तों को कम करने का प्रभाव हो। यदि अधिनियम के शब्द स्पष्ट हैं और उसके शब्दों के सादे और व्याकरणिक निर्माण पर केवल एक ही व्याख्या करने में सक्षम हैं, तो एक गैर-अस्थिर खंड निर्माण में कटौती नहीं कर सकता है और इसके संचालन के दायरे को सीमित नहीं कर सकता है। ऐसे मामलों में गैर-अस्थिर खंड को पूरी स्थिति को स्पष्ट करने वाले के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और यह समझा जाना चाहिए कि अधिनियम में विधायिकाद्वारा प्रचुर सावधानी के माध्यम से शामिल किया गया है , न कि ऑपरेटिव भाग के दायरे और दायरे को सीमित करने के माध्यम से। अधिनियमन का।"

(पृ 599-600 देखें)

(महत्व जोड़ें)

36. चंदावरकर सीता रत्न राव बनाम आशालता एस. गुरम (1986) 4 एससीसी 447 में रिपोर्ट की गई, इस न्यायालय ने कहा कि " अभिव्यक्ति 'इस अधिनियम में कुछ भी शामिल होने के बावजूद... अक्सर एक अनुभाग में जोड़ा जाता है संघर्ष की स्थिति में , धारा के अधिनियमित हिस्से को अधिनियम के प्रावधान या गैर-अस्थिर खंड में उल्लिखित अनुबंध पर एक अधिभावी प्रभाव देने की दृष्टि से शुरुआत। यह कहने के बराबर है कि इसके बावजूद अधिनियम का प्रावधान या गैर-अस्थिर खंड में उल्लिखित कोई अन्य अधिनियम इसके बाद के अधिनियम का पूर्ण संचालन होगा..." (पृष्ठ 477-478 देखें)।

(महत्व जोड़ें)

37. इसके अलावा, एजी वरदराजुलु एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य में इस न्यायालय ने (1998) 4 एससीसी 231 में रिपोर्ट दी , यह माना गया कि यह एक गैर-अप्रत्याशित खंड से निपटने के दौरान स्वागत योग्य है जिसके तहत विधायिका चाहती है किसी अनुभाग को अधिभावी प्रभाव देने के लिए , न्यायालय को यह पता लगाने का प्रयास करना चाहिए कि विधायिका किस हद तक किसी प्रावधान को किसी अन्य प्रावधान पर अधिभावी प्रभाव देने का इरादा रखती है। बेंच ने माधव राव सिंधिया बनाम भारत संघ एवं अन्य, [(1971) 1 एससीसी 85] में संविधान पीठ के फैसले में सिद्धांत का उल्लेख किया , जिसमें इस अदालत ने माना था कि गैर-अस्थिर खंड

एक बहुत ही शक्तिशाली खंड था जिसका उद्देश्य एक ही क़ानून या अन्य क़ानून के अन्य प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले हर विचार को बाहर करना था, लेकिन "उस कारण से ही हमें उस प्रावधान का दायरा सख्ती से निर्धारित करना चाहिए"। जब उक्त खंड वाला खंड किसी विशेष प्रावधान को संदर्भित नहीं करता है, जिसे वह ओवरराइड करने का इरादा रखता है, लेकिन आम तौर पर क़ानून के प्रावधानों को संदर्भित करता है , तो यह मानने की अनुमति नहीं है कि यह पूरे अधिनियम को बाहर करता है और अपने आप में अकेला खड़ा है (पृष्ठ 236 देखें)।

38. इस न्यायालय ने (2006) 10 एससीसी 452 में रिपोर्ट किए गए आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड बनाम सिडको लेदर्स लिमिटेड एवं अन्य के मामले में भी कहा था कि एक गैर-अस्थिर खंड के व्यापक आयाम को विधायी नीति तक ही सीमित रखा जाना चाहिए और इसे उस सीमा तक प्रभावी किया जा सकता है , जहां तक संसद का इरादा था और उसी से परे नहीं और एक गैर-अस्थिर खंड के प्रावधानों को समझने में , उस उद्देश्य और उद्देश्य को निर्धारित करना आवश्यक था जिसके लिए इसे अधिनियमित किया गया था (पृष्ठ 465 देखें) -6).

(जोर देने के लिए रेखांकित)

39. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम केरल राज्य एव अन्य में। (2009) 4 एससीसी 94 में रिपोर्ट की गई , इस न्यायालय ने दोहराया कि एक गैर-अस्थिर खंड की व्याख्या करते समय न्यायालय को यह पता लगाना आवश्यक है कि विधायिका किस हद तक इसे एक अधिभावी प्रभाव देने का इरादा रखती है।

40. इस कोर्ट द्वारा गैर-विषयक खंड के अभिप्राय और अर्थ पर व्यक्त की गई ऐसी सुसंगत राय के मद्देनजर हमारा विचार है कि संशोधित अधिनियम की धारा 7(3) में एक गैर-विषयक खंड का संचालन विषय होगा विधायिका की मंशा के अनुरूप , और इसकी व्याख्या अधिनियम की शर्तों और उस उद्देश्य के अनुरूप की जानी चाहिए जिसके लिए इसे अधिनियमित किया गया था।

41. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने यह तर्क देने के लिए इस न्यायालय के दो निर्णयों का उल्लेख किया कि धारा 7(3) में गैर-अस्थिर खंड अधिनियम के अन्य सभी प्रावधानों को पूरी तरह से खत्म कर देता है। वे निर्णय हैं: (ए) चंदावरकर सीता रत्न राव बनाम आशालता एस गुरम, (1986) 4 एससीसी 447,

(बी)भारत संघ एवं अन्य व . जीएम. कोकिल एवं अन्य, 1984 ए (सप्प) एससीसी 196। हालाँकि, इनमें से कोई भी निर्णय उत्तरदाताओं के तर्क का समर्थन नहीं करता है।

42. दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित फैसले में कहा कि धारा 7(3) में गैर-अस्थिर खंड को संशोधन अधिनियम के अन्य प्रावधानों को पूरी तरह से समाप्त करने के रूप

में पढ़ा जाना चाहिए और उप-प्रमुख जो संशोधन से पहले चुने गए थे अधिनियम ऐसे ही कायम रहेगा जैसे कि संशोधन अधिनियम पूरी तरह से अधिनियमित ही नहीं हुआ हो।

43. हालाँकि, ऊपर चर्चा किए गए इस न्यायालय के कई निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि धारा 7(3) में गैर-प्रमुख कारण उप-प्रमुख को "पद पर बने रहने" की अनुमति देने की सीमा तक सीमित होगा। इस तरह.. जैसे कि उक्त अधिनियम अधिनियमित ही नहीं किया गया हो।"

44. हमारे विचार में, 'पद पर बने रहना' का अर्थ यह होगा कि संशोधन अधिनियम में उप-प्रमुख के पद को समाप्त करने के बावजूद , जो लोग इस तरह के संशोधन से पहले उप-प्रमुख के रूप में चुने गए थे , वे पद पर बने रहेंगे। जैसे कि उप-प्रमुख के रूप में जब तक उसका कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता। सावधानी के तौर पर और इस बात पर ज़ोर देने के लिए कि उप-प्रमुख की निरंतरता केवल उप-प्रमुख के पद पर बने रहने तक ही सीमित है , अभिव्यक्ति 'यथातः' जोड़ी गई है।

45. प्रतिवादी का विपरीत तर्क और जो उच्च न्यायालय के साथ तौला गया , वह यह है कि उप-प्रमुख अधिनियम के पूर्व-मौजूदा प्रावधानों की धारा 82 और 83 के तहत सभी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग जारी रखेंगे , भले ही उन प्रावधानों को स्पष्ट रूप से हटा दिया जाए। संशोधन अधिनियम द्वारा प्रावधान. इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता|

46. यदि उस तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है , तो उस स्थिति में , जो प्रावधान संशोधन के माध्यम से स्पष्ट रूप से हटा दिए गए हैं , जैसे कि धारा 82 और 83 के पहले से मौजूद प्रावधान, पुनर्जीवित हो जाएंगे। धारा 9(2) और 9ए, संशोधन के माध्यम से लाई गईं और इस तरह प्रमुख का पद खाली होने पर जिला मजिस्ट्रेट को व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया (धारा)

9(2)] या जब प्रमुख कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है [धारा 9ए] अकार्यशील होगी। इसलिए, संशोधित अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या के लिए , धारा

7(3) में गैर-अस्थिर खंड को एक प्रतिबंधित अर्थ दिया जाना चाहिए ताकि संशोधित अधिनियम के अन्य प्रावधानों के साथ टकराव न हो।

47. संशोधन अधिनियम की धारा 7(3) में 'मानो उक्त अधिनियम अधिनियमित ही नहीं किया गया' अभिव्यक्ति केवल वहीं लागू होती है , जहां उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला अधिनियम 1961 के सामान्य संशोधन के माध्यम से उप-प्रमुख शब्द को लागू किया गया है।

48. इसलिए, हम धारा 9(2) और 9ए के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि करते हैं। हम उच्च न्यायालय के फैसले में दिए गए के विपरीत तर्क से सहमत नहीं हो सकते।

49. उपरोक्त तर्क के आलोक में, अपीलें स्वीकार की जाती हैं, इन सभी मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णयों को रद्द किया जाता है।

50, हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

बी.बी.बी. **अपील स्वीकार**